

सम्पादकीय

रूस और यूक्रेन के बीच जारी
युद्ध से उभरते सामाजिक
और प्रासंगिक सवाल

भारत समेत विश्व के कुछ चुनिंदा देशों द्वारा प्रयास के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूसी हमले की तीव्रता से प्रतीत होता है कि रूसी सेना इन हमलों की तैयारी पहले से ही कर रही थी और बड़े पैमाने पर हमले करने की योजना थी। हमलों की वजह से यूक्रेन से जनता का भारी पलायन हुआ है और लोग यूक्रेन से सटे हुए आसपास के देशों में शरण ले रहे हैं। अब तक लगभग 20 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं जिनमें से आधे लोगों ने पोलैंड में शरण ली है, जबकि शेष अन्य पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। हालांकि वर्तमान संघर्ष का कोई तत्काल उत्प्रेरक नहीं है और यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के निर्णय से रूस को उत्पन्न खतरे को ही हमलों की वजह माना जा रहा है। वैसे पिछले कीरीब दो दिनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से यह कहा जा रहा है कि फिलहाल वे नाटो में शामिल होने के अपने निर्णय को लेकर तटस्थ हैं, जिससे एक बार तो ऐसा लगा कि युद्ध थम जाएगा, परंतु रूस का इरादा कुछ और ही लग रहा है। माना जा रहा है कि रूस या तो यूक्रेन या उसके बड़े भाग पर कब्जा करना चाहता है या फिर रूस समर्थित रिहायशी क्षेत्रों को यूक्रेन से अलग कर उन्हें रूस का हिस्सा बनाना चाहता है। परंतु रूस को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी अपेक्षा के विरुद्ध उसे यूक्रेन की सेना व स्थानीय जनता से भारी प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका और अन्य देशों ने युद्ध रोकने व संघर्ष विराम के अनेक प्रयास किए, रूस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए, परंतु उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिसके परिणामस्वरूप रूस लगातार अपने हमले तेज करता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी युद्ध रोकने के प्रयास किए गए, पर सुरक्षा परिषद में रूस द्वारा वीटो किए जाने की वजह से इस मामले में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हमले की निर्दा करते हुए प्रस्ताव पारित किया है, परंतु महासभा की शक्तियां सीमित होने के कारण संघर्ष रोकने में उसका कितना प्रभाव होगा, अभी यह आकलन करना मुश्किल है। विश्व के समक्ष चुनौतियां इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर से विश्व के समक्ष अनेक चुनौतियां व प्रश्न पैदा किए हैं। क्या कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र जब चाहे किसी भी कमज़ोर देश पर कोई भी कारण या बहाना बना कर हमला कर जितनी चाहे जान-माल की हानि कर सकता है? क्या किसी भी कारण से एक देश पर किए गए आक्रमण को न्यायोचित ठहराया जा सकता है और क्या विश्व समुदाय द्वारा बनाए गए कानून व संस्थाएं आक्रमण रोकने में असहाय हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि देशों के अपने राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक व अर्थिक हित होते हैं। परंतु उन हितों को साधने के लिए किसी संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र पर आक्रमण कर उसे तबाह करना, उसकी भूमि और संसाधनों पर कब्जा करना, निर्दोष जनता को मारना और उन्हें अपना घर व देश छोड़े पर मजबूर करना कितना न्यायोचित है दुर्भाग्य है कि यूक्रेन के आम व्यक्तियों को देश की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ रहा है विदेश में रह रहे लोग देश के लिए लड़े के लिए वापस आ रहे हैं। युद्ध की भयावहता युद्ध में मारे गए व घायल लोग, उनके बिलखते परिजन व रोते बच्चों की दुर्दशा देख कर हृदय को असहनीय पीड़ा होती है कि किस प्रकार एक देश द्वारा अपने हितों को साधने के लिए एक खुशहाल देश को बर्बादी की राह पर ला दिया गया। रूस ने यह हमला करके अंतरराष्ट्रीय बल निषेध, मानव अधिकार व आपराधिक कानूनों का घोर उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र देशों की समानता, संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता व क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित है और देशों को एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है। परिषद द्वारा मामले का संज्ञान लेने तक किया जा सकता है। निषेध कानून, बल्कि आम नागरिकों पर हमला कर वैश्विक मानवीय व आपराधिक कानूनों का भी उल्लंघन किया है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण ने न केवल यूक्रेन में भीषण मानवीय त्रासदी को जन्म दिया है, अंतरराष्ट्रीय कानून और संबंधित संस्थाएं इस प्रकार की घटनाएं निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय कानून व संस्थाओं की प्रासंगिकता व विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि इस संघर्ष से अंतर्राष्ट्रीय कानून व संस्थाओं की प्रासंगिकता व विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए
आक्रमण से दुखी होंगी व्यास
और टाल्सटाय की आत्माएं

रुस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले को दो सप्ताह हो चुके हैं। विकट धर्वंस जारी है। संपदा और संसाधनों की भारी क्षति के साथ यूक्रेन के दो हजार से अधिक लाख लोग पलायन कर चुके हैं। यूक्रेनी राजकीय सूत्रों के अनुसार उहोंने पांच हजार से अधिक रुसी सैन्यबलों को मारा है और उनके सेन्य उपकरणों को नष्ट किया है। यह आंकड़ा कुछ अतिरिक्त भी हो सकता है, किंतु रुस की क्षति हुई अवश्य है। यूक्रेनी महिलाएं तक युद्धरत हैं। वे बम बना रही हैं। टैंकों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यूक्रेन के धर्वंस के साथ साथ रुस का भी प्रतिरिद्दिन लगभग सब लाख करोड़ रुपया युद्ध व्यय आ रहा है। रुस में युद्ध के विरुद्ध जन प्रदर्शन हो रहे हैं। दुर्भाग्यवश इस युद्ध की चपेट में आकर एक भारतीय छात्र का निधन हो गया, जबकि एक घायल हो गया। हालांकि वहां पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्रों पर भी युद्ध का संकट था, परन्तु अच्छी बात यह हुई कि भारत सरकार वहां से आने के इच्छुक लगभग सभी छात्रों को लाने में सफल रही। फिर भी वहां मानवता कराह रही है। परमाणु युद्ध की आशंका से सपूत्रा विश्व सशक्तिकृत है। एक दशक पूर्व इसी रुस में इस्कान यानी इंटरनेशनल सोसायटी फार वृद्धि कांसेशने से बोर्ड संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज द्वारा विरचित श्रीमद्बगवद्गीता के रुसी अनुवाद और विशेषण 'भगवद्गीता एज इट इन पर वहां प्रतिबंध लगाए जाने की बयार चली थी। सरकारी अभियोजक इसे प्रतिवंधित करने के लिए अदालत गए थे। उनका सोच था कि गीता उग्रवाद और युद्धोन्माद बढ़ाने वाला ग्रंथ है। आखिरकार वहां के हिंदू, अन्यान्य प्रबुद्ध लोग और भारत सरकार व जनमानस का रुख देखकर वह बयार थमी। पर इतना तो सच ही है कि कभी इतनी शांतिप्रियता की लाठी भांजने वाले आज एक संप्रभु देश पर केवल इसलिए आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि वह उनके अनुसार, अमेरिका नीत 'नाटो' सेन्य संगठन का सदस्य बनने की सोच रहा था और अपने देश में शायद नाटो का सेन्य प्रशिक्षण केंद्र खुलवाता। 19वीं सदी में ने पोलियन द्वारा रुस पर आक्रमण के बाद तत्परिणामी विभीषिका देखकर रुस के महान साहित्यकार लियो टाल्सटाय ने 'वार एंड पीस' (युद्ध और शांति) नामक कालजीयी कृति सूजित की, जिसमें दर्शन, अद्यात्म, इतिहास, सामाजिकता लिए परिवर्गिक जीवन की खुशहाली को रेखांकित किया गया। लेखक युद्ध क्षेत्रों में भी गए और वास्तविकताएं देखीं। वे इसी रुसी धरती के सपूत्र थे, जहां के शासक आज अत्यंत लचर आधार पर विश्व को युद्ध की विभीषिका में झोंके दे रहे हैं।

रुपे कार्ड और यूपीआइ को प्रोत्साहन देकर भारत ने स्वयं को उस स्थिति से बचा लिया जिससे इस समय रूस जूझ रहा है

बीते दिनों मास्को सहित रूस के कई शहरों में मेट्रो स्टेशनों से लेकर एटीएम कियोस्क जैसे सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की लंबी-लंबी कतारों की फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल थीं। भीड़ का एक बड़ा कारण यह था कि एप्ल, गुगल, वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और पेपल जैसी कंपनियों ने रूस में अपना परिचालन बंद कर दिया था। यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में लाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण इन कंपनियों ने यह कदम उठाया था। लोग मेट्रो जैसी सेवाओं के लिए आनलाइन भुगतान के अभ्यस्त हो गए थे, लेकिन एकाएक लगे इस प्रतिबंध ने उन्हें नकदी का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। इसी कारण मेट्रो स्टेशनों पर लंबी कतार लग गई। तामाम अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के भुगतान के लिए बढ़ी नकदी की जरूरत से एटीएम कियोस्क के बाहर भी लोग कतारबद्ध दिखे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भुगतान नेटवर्क से जुड़ी पश्चिमी कंपनियों ने अपनी इन सेवाओं को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रखा है एवं लेनदेन पर आधात किया है। इस परिदृश्य ने एक नई बहस छेड़ दी है कि पश्चिमी संस्थाओं पर पूरी तरह निर्भरता अपनी वित्तीय संभुता के लिए कितनी घातक है यदि भारत के समक्ष ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुईं तो उस स्थिति में क्या होगा शुक्र है कि भारत के संदर्भ में इसका जवाब वैसा नहीं होगा जैसा रूस के मामले में देखेने को मिला। इसका श्रेय जाता है भारत सरकार की दूरदर्शी नीतियों को, जिसने समय से रुपे कार्ड और यूपीआइ जैसी भुगतान प्रणालियों को न केवल अपनाया, बल्कि उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन भी प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआइ की यह दोहरी पेशकश ऐसे किसी भी संकर में भारत के लिए वरदान सिद्ध होगी। वास्तव में पैमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी वित्तीय भुगतान से जुड़ा ढाचा किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। कंपिय कारणों से भारत पारंपरिक रूप से नकदी प्रधान अर्थव्यवस्था रहा। इसमें नकदी के विकल्प रूप में अपनाई जाने वाली प्रणाली के उपयोग में एक निश्चित लागत सबसे बड़ी बाधा रही। जैसे वीजा या मास्टरकार्ड से होने वाले कार्ड भुगतान पर कुछ प्रतिशत राशि इन कंपनियों की झोली में जाती है। यह पहलू भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण की राह में एक बड़ी बाधा बना रहा। मोदी सरकार ने इस अवरोध को चिन्हित कर रुपे के तौर पर एक शुक्र मुक्त पहल की। इसका असर भी दिखा। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 तक देसी डेबिट कार्ड बाजार में रुपे कार्ड की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि 2017 में यह 15 प्रतिशत ही थी। इस बढ़ोत्तरी में एक निर्णायक पहल प्रधानमंत्री जन धन योजना का भी रहा, जिसके अंतर्गत खाताधारकों को रुपे कार्ड ही जारी किए जाते हैं। हालांकि

प्राप्त हो रहा है, बल्कि इससे हर साल हजारों करोड़ रुपये की बचत भी हो रही है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआइ आत्मनिर्भर भुगतान प्रणाली से जुड़ी भारत सफलता गाथा का दूसरा अद्याय है। आज जब बैंकिंग सुविधा हमारे फोन में सिमट गई है तो यूपीआइ वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाने के महत्वपूर्ण आधार के रूप में उभरा है। आकड़े इसकी सफलता स्वयं कहते हैं। वर्ष 2014 तक जीडीपी में खुदरा डिजिटल भुगतान की नाममात्र की हिस्सेदारी थी, जो 2021 में बढ़कर 47 प्रतिशत तक पहुंच गई। यूपीआइ ने वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित एवं आसान बनाने के साथ ही नकदी पर निर्भरता घटाने में भी नाटकीय भूमिका निभाई है। वर्ष 2014 में खुदरा लेनदेन में एटीएम निकासी की हिस्सेदारी 88 प्रतिशत थी, वह दिसंबर 2021 में घटकर 22 प्रतिशत रह गई। यानी यहां भी दोहरा फायदा है। यूपीआइ से जहां बैंक-एटीएम गाले नकदी लाजिस्टिक्स पर आने वाला खर्च घटा है, वहीं वित्तीय लेनदेन सुरक्षित होने और समूचे तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने वाला भी सिद्ध हुआ है। इसीलिए दुनिया के कई देश यूपीआइ के प्रति आर्किट दिख रहे हैं। यूकैन पर हमले के बाद रूस को जिस प्रकार के वित्तीय प्रतिबंधों को सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए भारतीय नीति-नियंताओं की सज्जबूझ की दाद देनी होगी कि उहोंने वित्तीय मोर्चे पर आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को समस्या भांपकर उस दिशा में कदम बढ़ा दिए थे। अमेरिका और अन्य पश्चिमी वित्तीय दिग्गज कंपनियों के ऐसे रैये के कारण अब दुनिया के कई देशों में उनके प्रति आशकाओं का जन्म लेना स्वाभाविक है। ऐसे में यह भारत के लिए उचित अवसर है कि वह रुपै और यूपीआइ के वैश्विक विस्तार के प्रयासों को और गति दे। मोदी सरकार पहले ही इन कोशिशों में लगी है। संयुक्त अखबार अमीरत जैसे देश ने रुपै कार्ड को व्यापक स्वीकार्यता दी है। दक्षिण-पूर्वी एशिया और खाड़ी के कई देशों में उसे अपनाने की तैयारी हो रही है। वहीं तपाम देश भारत की प्रेरणा से अपनी स्वतंत्र प्रणालियां विकसित करने के इच्छुक हो सकते हैं। अपने अनुभव एवं दक्षता से भारत इन देशों की दबदब के लिए आगे आ सकता है। एक ऐसे दौर में जब वित्तीय लेनदेन का पूरा तानाबाना बदल गया है और भविष्य की लड़ाइयों में तकनीक की भूमिका अहम होती जाएगी, उस स्थिति में भारत की रुपै और यूपीआइ जैसी पहल उसे वित्तीय आत्मनिर्भरता का आवरण प्रदान करने के साथ ही विश्व को नई राह भी दिखाएंगी।

मास्को या वाशिंगटन में से किसी एक विकल्प को चुनने का अमेरिकी दबाव भारत-अमेरिका रिश्तों में कड़वाहट ही घोलेगा

A political cartoon by Amrit Singh. It features a caricature of Narendra Modi on the left, looking up at a much larger, bearded version of himself on the right. The larger version is dressed as a sage or Yogi, wearing a dhoti and a tilak, and has a halo above his head. He is holding a book. The background is dark and textured.

को सुधारने की प्रायत्तिकता देने वाला बाइडन प्रशासन चीनी आक्रमकता के मामले में भारत के सार्वजनिक समर्थन से बचता रहा। इतना ही नहीं बाइडन ने चीनी आक्रमकता को हिंद-प्रशांत रणनीति का हिस्सा न मानकर भारत के साथ नियत्रण रेखा से जुड़ा मसला बताया। चीन तो छोड़िए, पाकिस्तान के मामले में भी टीम बाइडन ने भारत को ठोस समर्थन नहीं दिया। 'एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी' के रूप में वह पाकिस्तान पर निरंतर दांव लगा रहा है। वह भी तब जब पाकिस्तान के पिंडुओं यानी तालिबान के हाथों उसे अफगानिस्तान में अपमानजनक हार मिली। पाकिस्तान पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाने में बाइडन की नाकामी के चलते ही वह अभी तक आतंकी देशों की अमेरिकी सूची से बाहर है। इसके बावजूद टीम बाइडन यहीं चाहती है कि यूक्रेन मसले पर भारत उनका पुरजोर समर्थन करे। यह सही है कि अमेरिका भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनता जा रहा है, लेकिन दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कवच बनता आया रूस भी हमारा उतना ही महत्वपूर्ण मित्र है। ऐसी स्थिति में क्या भारत पश्चिम के साथ मिलकर उस देश के खिलाफ मतदान करता, जो ब्रिटोस मिसाइल से लेकर परमाणु पनडुड़ी जैसी तकनीक और रक्षा साजेसामान की आपर्ति

भारत से हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे रूस यूक्रेन युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होगा असर

आदि महांगे हो जाएंगे, जो सेमीकंडक्टर तकनीक पर निर्भाव है। उल्लेखनीय है कि वाहनों की दृष्टि से भारत विश्व का पांचवां बड़ा बाजार है। आशंका है कि जीडीपी में 7.1 प्रतिशत योगदान करने वाला हमारा आटोमोबाइल से कटर प्रभावित होगा। यूक्रेन युद्ध के बाद एचडीएफसी बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में वित्ती वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 8.2 प्रतिशत से घटाकर 7.5 से 7.8 प्रतिशत तक रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बदलती परिस्थितियों में महांगई को रोकने के लिए आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति के प्रविधानों को इस प्रकार बदलना होगा कि ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तन से आम आदमी की जब पर कम से कम असर पढ़े। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के बीच भारत मास्को और वाशिंगटन के बीच संतुलन स्थापित कर युद्ध के प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों को थोड़ा कम कर सकता है। भारत और रूस के बीच होने वाला व्यापार आठ

